प्रतिरक्षा भारती
Pratiraksha Bharti

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ का मुख्य पत्र

जनवरी २०२४ • वर्ष-विंशति (२०) • अंक ०१ • मूल्य : १० • वार्षिक मूल्य : १२०

महामंत्री श्री मुकेश सिंह द्वारा यूनियन सत्यापन के सम्बन्ध में पुणे के कार्यकर्ताओं से वार्ता

G.C.F. जबलपुर यूनियन द्वारा यूनियन सत्यापन हेतु जनसम्पर्क अभियान

भा.प्र.म. संघ के पदाधिकारियों द्वारा सदस्यता सत्यापन हेतु बैठक

देहरादून

ओ.सी.एफ. शाहजहाँपुर

आई.डब्ल्यू.ओ. मुम्बई

सम्पादक की कलम से

– श्री साधू सिंह

प्रिय मित्रों

आप सभी एक महाअभियान में पिछले एक माह से सदस्यता सत्यापन में बहुत मेहनत से लगे हुए थे। अपेक्षित सफलता मिली या नहीं मिली यह हम सबके हाथ में नहीं होता, फिर भी हमने बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। आप सभी को बधाई देना चाहता हूँ और भविष्य के लिये शुभकामनाएं भी देता हूँ। सदस्यता सत्यापन से सही मूल्यांकन होता है हम किस स्थिति में हैं। इसके बाद भविष्य में आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। हमने लगातार प्रयास किये फिर भी कुछ स्थानों पर जहां आज से 20 साल पहले थे वहीं आज भी है इन स्थानों पर हमें कुछ सोचना होगा। खासकर उन स्थानों पर जहां हम 15 प्रतिशत से नीचे 2005 में थे, 2010 में थे, और आज 2024 में भी वहीं पर हैं। इन स्थानों के पदाधिकारियों को सोचना होगा कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। हमें जुनूनी कार्यकर्ताओं की जरूरत है। जिनमें जुनून मर चुका है उनके पदों पर दूसरे कार्यकर्ताओं को स्थापित करना चाहिये या उन्हें स्वयं पद छोड़ देना चाहिये। बहुत से स्थानों पर हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा किया न केवल यूनियन की स्थापना की बल्कि दूसरे संगठनों को नेस्तनाबूत भी किया जैसे MES में हमारे लोगों ने बहुत अच्छी परफार्मेन्स दिखाई। लेकिन बहुत बड़ा सेक्टर आज भी ऐसा है जहां पर हम नहीं है जैसे महाराष्ट्र,गुजरात, गोवा, केरल, पूर्वोत्तर राज्यों में अभी भी MES में काम खड़ा करना होगा। इतने स्थानों पर हमारी अनुपस्थिति एक संगठन को बहुत लाभ पहुंचाती है। इन स्थानों पर आपको ही काम खड़ा करना होगा इन प्रदेशों के कार्यकर्ताओं को ही जूझना होगा। यह विचार छोड़ना होगा कि हमारा काम एक महासंघ होने के कारण ग्रीवांस हल करना है संगठन खड़ा करना या संगठन को मजबूत करना प्रदेश का काम है। शून्य से प्रारम्भ होने वाला संगठन आपको ही खड़ा करना है। उसे मजबूत भी बनाना है ग्रीवांस भी आपको ही हल कराना है सब कुछ आपको करना है आप BMS हो यह मानकर काम करना होगा। पिछले चुनाव और इस चुनाव का तुलनात्मक अध्ययन करना होगा कि पिछले बार हम कहाँ थे और अब कहाँ है। बहुत से स्थानों पर खासकर आयुध निर्माणियों में हम पीछे हुए है जहाँ पर हमें 60 प्रतिशत तक सदस्यता थी घटकर 30 प्रतिशत के आसपास आ गए हैं। 51 प्रतिशत से घटकर 29 प्रतिशत पर आ गए। ऐसे भी स्थान है जहाँ हम 30 से 40 प्रतिशत तक थे आज 10–11 प्रतिशत पर आ गए। सोचना होगा ऐसा क्यों हुआ सही ढंग से आत्ममंथन करने पर स्तिथि स्वयं आपको पता चल जाएगी। आयुध निर्माणियो में हम दूसरे से तीसरे स्थान पर आ गए आत्ममंथन करने की जरूरत है जिस संगठन ने कर्मचारियों और अपने संस्थान के साथ गद्दारी की वह हमसे आगे है जबकि कारपोरेशन की लड़ाई को ईमानदारी से हमने लड़ा सड़क से न्यायालय तक हम गए। फिर भी हम पीछे आखिर क्यों ? कुछ स्थानों पर हम अपनी गलतियों के कारण नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन भी नहीं बचा सके, हम चुनाव का बहिष्कार लोकल लेवल पर निर्णय लेकर करने लगे। महासंघ से पूछना भी जरूरी नहीं समझा। हमें अनुशासन में रहना होगा। कुछ स्थानों पर महासंघ के भी अनिर्णय की स्थिति में रहना या गलत लोगों पर भरोसा करना भी हमारे लिए ठीक नहीं रहा त्वरित निर्णय लेने की परंपरा डालनी होगी। कार्यकर्ताओं को समय पर उनकी गलती का अहसास कराना होगा केवल दण्डात्मक कार्यवाही ही उचित नहीं होगी, अपितु लगातार गलतियों को नजरंदाज करना भी ठीक नहीं होगा। हम कितने सही रास्ते पर है और कितना गलत इस पर भी बिचार करना होगा। कुछ लोग संगठन के बारे में ऐसी सोच रखते है कि छोटा परिवार सुखी परिवार अर्थात जितनी कम संख्या है उतनी ही कम समस्यायें रहेंगी और मान्यता प्राप्त महासंघ की यूनियन होने का लाभ मिलता रहेगा। ऐसी सोच कानों तक आती है ऐसे लोगो को छांटना होगा। निष्क्रिय पदाधिकारियों को सक्रिय होने की जरूरत है। अभी तक के चुनाव परिणामों में हम दूसरे स्थान पर है जहां–जहां पर अभी चुनाव नहीं हुए वहां पर अपने लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी DRDO, Air Force, Navel, DGQA और MES, EME में सभी को ध्यान देने की जरूरत होगी।

अपने सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपने नई टीम के साथ बैठकर संगठन को सर्वोपरि मानते हुए काम किया सभी वरिष्ठ जनों के प्रति आभार और बधाई शुभकामनाएं। निरन्तर बिना रुके बिना थके भारतीय मजदूर संघ के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाना है और **आगे बढ़ो संघर्ष करो का नारा अपनाना है**।

।। जय हिन्द, जय भारत ।।

बड़ों का योगदान (संगठनात्मक संस्कृति)

— सी. के. सजीनारायण

हमारा एक आजीवन काम है। हमारे संगठन में केवल प्रवेश है, कोई निकास नहीं, सेवानिवृत्ति नहीं। तो बड़ों को हमेशा एक सम्मानजनक स्थान होगा। इस को ध्यान में रखते हुए, बड़ों को भी जिम्मेदारी के साथ व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का योगदान छोटों को ढालना, मार्गदर्शन और प्रशिक्षित करना है। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को गुणों को प्रोत्साहित करना और दोषों को हतोत्साहित करना चाहिए, जब यह अपने संज्ञान में आते हैं तो वरिष्ठ पदाधिकारियों को संगठनात्मक संस्कृति, वित्तीय अनुशासन, श्रम संगठन की कुशल गतिविधियाँ, श्रम संगठन की गतिविधियों में झुझारूपन आदि पर मार्गदर्शन देना चाहिए। वरिष्ठ पदाधिकारियों को कार्यकर्ताओं के साथ आपस में मिलना या दुःख और सुख परस्पर साझा करना चाहिए। खुले दिमाग और दृष्टिकोण के साथ बिना पक्षपात या पूर्वधारणा से व्यवहार करना चाहिए। वरिष्ठ कार्यकर्ता द्वारा निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को सहायता और मार्गदर्शन देना चाहिए, और नेता मात्र नहीं बनना। उन्हें स्नेह और प्रेरणा देना चाहिए। एजेंडा के बिना विभिन्न स्तरों के कार्यकर्ताओं के साथ बैठना।

जब वरिष्ठ लोग अपने से छोटे कार्यकर्ता को बढ़ावा नहीं देते तो क्या होता है? एक बार एक वरिष्ठ वकील ने अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताया। जब उसने वकालत शुरू किया था, तो पहले पांच साल के लिए वह केवल अपने सीनियर का फाइल ले जाता था। सीनियर ने उसका विकास नहीं किया। एक दिन जब सीनियर उस जगह से दूर था, तो उसका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लेकिन केवल एक स्थगन पाने के लिए। फिर ग्राहक आया और सीनियर के बारे में पूछा, तो उसने जवाब दिया कि वह नहीं है। तब ग्राहक ने पूछा कि फिर क्या होगा, उन्होंने कहा मैं यह तर्क करूंगा। तब ग्राहक डरा था और कहा कि केवल वरिष्ठ मामले तर्क करना चाहिए और कहा कि वह मामला तर्क नहीं करने के लिए फीस देगा। इस प्रकार, मामला तर्क नहीं करने के लिए उसको अपने जीवन में पहली फीस मिली।

वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शक होना चाहिए और संगठन में शक्ति केन्द्रों या 'बॉस' के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए। हमारे अधिकारी निरीक्षक या लेखा परीक्षक नहीं हैं, बल्कि वे हमारे कार्यकर्ताओं को मदद करनेवाले हैं। अगर अपने पद के लिए आदर और डर कैडर के मन में बनाया है, तो वह तभी तक रहते हैं जब तक आप उस विशेष पद पर हैं। लेकिन जब व्यक्तिगत स्नेह आप देते हैं, तो उसके बाद भी वह संबंध जारी रहेगा। एक छोटे से गाँव में एक चोर की कहानी है। चोर शारीरिक दृष्टि में बहुत मजबूत था और उसकी आपराधिक गतिविधियों में खुलेआम में लिप्त था। लोग भी उसके खिलाफ शिकायत करने के लिए डरते थे। वह एक लंबे समय के लिए इस तरह बना रहा। एक दिन रात में वह पूरी तरह से नशे में था और सड़क पर पड़ा था। यह देखकर कुछ युवाओं ने सोचा कि यह सही मौका है उसे संभालने के लिए। वे उस पर कूद गये और उसे बुरी तरह पीटा। जब उसके हाथ और पैर टूट गये, तो वे उसे सड़क पर छोड़ कर चले गए। सुबह लोगों ने मजबूत डाकू को नीचे असहाय स्थिति में देखा। पहले वे निकट जाने में डरते थे, लेकिन दिलचस्पी से पास गये, तब उनमें से कुछ लोगों ने उसकी पिटाई शुरू कर दी। कुछ लोग एसिड लाये और उसकी आंखों में डाल दिया, वह अंधा हो गया और अपने जीवन के बाकी समय कुछ भी नहीं कर सकता था और भीख माँग मांग कर जीवन बिता सकता था। जब वह घर गया तो लोगों ने उसे गाली दिया और उसके चेहरे पर थूक कर भगा दिया।

एक शहर के केंद्रीय मैदान में रहकर भिखारी ने अपने अंतिम दिनों में एक इच्छापत्र लिखा। वह अपने बड़े बेटे को दाहिने पक्ष और अगले बेटे के लिए मैदान का बाई पक्ष आवंटित कर दिया जो भी माँगने के लिए था। बड़ों उनके अनुयायियों को केवल खोखला विरासत माँगने कोणी नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी अगली पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक संस्मरण छोड़ना चाहिए।

कई स्थानों पर जूनियर कार्यकर्ताओं के माध्यम से निचले स्तर के संगठनात्मक काम लेना वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की समझ के पार है। सफेद और काले बालों का मिश्रण होना चाहिए। 'युवा कंधों पर पुरानी मस्तिष्क' का मतलब है, पुराने मस्तिष्क से दिशा पता चलती है और युवा कंधों पर इसे लागू करना चाहिए। वरिष्ठों को संगठन की गतिविधियों के लिए बहुत ज्यादा नहीं लगे रहना चाहिए। अच्छा नेतृत्व का मतलब यही है, अनुयायियों को अधिक से अधिक अवसर देकर उनकी क्षमता का उपयोग करने वाले होना चाहिए।

दूसरी तति का निर्माण करना— अगला नेतृत्व

मोहनजी भागवत खुद अपने अनुभव के बारे में बता रहे थे। जब दत्ताजी दिडोलकर एक संघ कार्यक्रम के लिए आये थे, तो

मोहनजी भागवत संघ गीत गायक थे। कार्यक्रम के बाद दत्ताजी ने पूछा कि वह कितने साल से कार्यक्रम के लिए गीत गा रहे हैं। मोहनजी ने कहा दो साल। तब दत्ताजी ने पूछा, पिछले दो वर्षों में भी आपने किसी को अपनी जगह विकसित नहीं किया हैं?

भा.म.सं., अ.भा.वि.प. जैसे संगठन काडर आधारित जन आंदोलन हैं। अगले नेतृत्व या दूसरी पंक्ति के नेतृत्व के बारे में क्या हैं? नेतृत्व की औसत उम्र कम होनी चाहिए। नए श्रमिक नए विचार लेने में 'ब्लोटिंग पेपर' की तरह हैं। पुराने श्रमिक सिक्त (soaked) हैं और दाग नहीं हो सकता। कुछ अपवाद हो सकता है। पदाधिकारियों के बीच वरिष्ठ–कनिष्ठ अनुपात को बनाए रखना है। इसके लिए दूसरी पंक्ति के कार्यकर्ताओं को हमेशा विकसित किया जाना चाहिए। हमेशा सोचना चाहिए कि दूसरी पंक्ति के नेतृत्व और पदाधिकारियों के अगले दल का निर्माण कैसे कर सकते हैं। कनिष्ठ श्रमिकों में विश्वास और भरोसा रखो और साथ ही उन पर एक नजर रखना चाहिए। मोहनजी भागवत ने कहा कि नई पीढ़ी के लिए काम स्थानांतरण करना चाहिए। दूसरी लाइन के बीच काम विभाजित और विकेंद्रित करना चाहिए। केवल उनको प्रोत्साहित करें जो दूसरी पंक्ति के नेतृत्व निर्माण में लगे हुए हैं। नेहरू के समय पर सवाल उठा था कि नेहरू के बाद कौन, जिसके लिए कई लोग जवाब नहीं दे सके। लेकिन सुदर्शनजी उनके उत्तराधिकारी मोहनजी भागवत के बारे में कहा कि मोहनजी द्वारा किया गया हर संघ काम में एक 'मोहनजी स्पर्श है।

''मुद्रराक्षसं'' नाटक में, अमात्य राक्षस, शत्रु राजा मलयकेतु का मंत्री था। अमात्य कुशल था हालांकि दुश्मन होने पर भी। इसलिए उसे खतम करने के बजाय, कार्यकुशलता द्वारा चाणक्य ने उसे अपने पक्ष में लाया और उसे देश का मंत्री बनाया।

उत्तराधिकारियों के लिए खोज

जिम्मेदारी का बदलाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया होनी चाहिए। दूसरी पंक्ति को जिम्मेदारी सौंपना चाहिए। उसके लिए भा.म.सं. का फैसला है कि:

1. भा.म.सं. के शीर्ष लोग ज्यादा ट्रेड यूनियन जिम्मेदारियों की बहुलता से (multiplicity of union responsibilities) बचना चाहिए ताकि नए कार्यकर्ताओं को अधिक अवसर मिल जाएगा। वरिष्ठ पदाधिकारियों को नए कार्यकर्ताओं को समायोजित करने के लिए रास्ता देना चाहिए।

2. इसी तरह एक ही जिम्मेदारी में दो से अधिक लंबी अवधि के लिए जारी नहीं रखना है। लंबे समय के लिए अपने पद पर अटकना नहीं है और जल्दी से नए कार्यकर्ताओं को रास्ता देना है। नए कार्यकर्ताओं को समायोजित करने लिए, निरंतरता साथ परिवर्तन होना चाहिए । पदाधिकारियों में आवधिक स्थानांतरण भी आवश्यक है। सभी पदाधिकारियों को साथ नहीं बदलना चाहिए। राज्य सभा के तरह होना चाहिए, जहाँ हर दो वर्ष में एक–तिहाई का परिवर्तन होता हैं।

डाक्टरजी ने ऐसे कार्यकर्ताओं को विकसित किया जो उनसे अधिक जानता था। उन्होंने अपने से अधिक सक्षम श्रीगुरुजी को उठाया और अपने उत्तराधिकारी के रूप में बनाया। इसी प्रकार श्री रामकृष्ण – विवेकानंद का उदाहरण है। हमारे पुराने कार्यकर्ताओं ने यह किया है, तो वे हमारे महान नेता थे। विवेकानंद ने कहा कि मैं सौ ऊर्जावान युवाओं को चाहता हूँ, तो मैं समाज को बदल सकता हूँ। हमको समर्पित कार्यकर्ताओं की एक सेना की आवश्यकता है। केवल वरिष्ठ कार्यकर्ता बड़ी यूनियनों का नेतृत्व कर सकते हैं, यह मिथक कई उद्योगों में खण्डन किया है, जैसे केरल में आई.आर.इ. में केवल स्थानीय स्तर पर ऊर्जावान कार्यकर्ताओं के भरोसे भा.म.सं. नंबर एक ट्रेड यूनियन के रूप में पहचाना गया था। उनहोंने अन्य यूनियनों के बड़े नेताओं को हराया। स्थानीय कार्यकर्ताओं को संगठन में उनकी दक्षता दिखाने के लिए अवसर देना है, तो आप चमत्कार देख सकते हैं।

एक बार टाइम्स इंडिया ने कहा कि, भाजपा एकमात्र पार्टी है जो पीढ़ियाँ बनाती है। दस साल के भीतर इसके कई अध्यक्ष बन गये। केरल में ट्रेड यूनियन के इतिहास के विषय पर शोध करने वाले एक विद्वान् ने सभी ट्रेड यूनियनों में कई नेताओं का इंटरव्यू किया। वे भा.म.सं. के विषय में चकित थे और पूछा कि यह कैसे संभव है कि विभिन्न स्तरों पर उनके बहुत से युवा नेता अन्य ट्रेड यूनियनों के सुव्यवस्थित वरिष्ठ नेताओं को हरा सकते हैं?

सूर्यनारायण रावजी कहते हैं, किसी को मुख्यशिक्षक या कार्यवाह के रूप में चुना है, तो तुरंत ही उसका पहला प्रयास अगले उत्तराधिकारी के लिए खोज करना होना चाहिए।

हमारी दूसरी लाइन कहाँ है? यह हमेशा एक मूल सवाल है। एक आयोजक को माना जाता है कि कितने नए कार्यकर्ताओं के परामर्शदाता (mentor) है। यदि नये कार्यकर्ताओं को नहीं बनाया जाता है, तो संगठन मौजूदा लोगों के साथ दखल देते हुए एक बदतर स्थिति में पड़ सकता है। हर बार स्खलित लोगों को नष्ट करते हैं और केवल ''उपलब्ध में सबसे अच्छा'' (available best) की पसंद है। सर्वश्रेष्ठ को जिम्मेदारी देना हैं।

भा.म.सं. में ठेंगड़ीजी खुद बिना जिम्मेदारी के मार्गदर्शन करने का एक उदाहरण था। उन्होंने पदों के बारे में कोई चिंता नहीं दिखाया। ठेंगड़ीजी भा.म.सं. में सबसे प्रतिष्ठित है, लेकिन वह किसी भी पद में नहीं थे। ❐

आपातकाल और ठेंगड़ी जी का सान्निध्य

– केशव पांडुरंग गोखले
पुणे (महाराष्ट्र)

1975–76 के आपातकाल में अनेक बार मा. दत्तोपंत ठेंगड़ी जी की रहने की व्यवस्था मुंबई की उपनगरी अंधेरी में हमारे घर में हुई थी। घर काफी बड़ा था जिसमें प्रकाश और हवा की कोई कमी नहीं थी। हमारे घर के सभी लोग उन्हें पंत नाम से पुकारते थे। उनके घर में होने के कारण संबंधों में घनिष्ठता बढ़ी। आज भी उन 40 वर्षों पूर्व की यादें ताजी लगती हैं।

परहित चिंता प्रधान– किसी भी परिवार में रहते समय उनका कहना था कि उनके वास्तव्य के कारण परिवारवालों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। मुंबई में पानी की कमी होने के कारण स्नान करते समय सावधानी से पानी का उपयोग करना, यजमान को लोकल पकड़नी पड़ती है। इसलिए अथितियों ने उनके बाद में स्नान करना, सारा व्यवहार अपने घर में जैसा हम करते हैं वैसा ही इस परिवार के साथ रहते समय करना ऐसी बातें पंत अपने सभी कार्यकर्ताओं को पहुँचते ही कहकर उन्हें सतर्क कर देते थे।

1 परिवार के साथ एकात्मता– मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटियाँ और मेरे माता–पिता इन सभी से पंत बड़ी आत्मीयता से बातें करते थे। सबके साथ अपनत्व प्रस्थापित करने में वे कुशल थे। उनमें संभाषण करने की कला विद्यमान थी। हम भी नागपुर के ही होने के कारण पुरानी यादों का उल्लेख करने में समय आनंदपूर्ण वातावरण में कैसे बीत जाता था, इसका पता ही नहीं चलता था।

संगठन और समाज पर विश्वास– आपातकाल में एक बार एक कार्यकर्ता ने आवेश में आकर बात करते–करते कहा कि उस समय के अपने देश के प्रधानमंत्री का कोई घातपात हुआ तो अच्छा ही होगा। पंत ने उसके इस कथन से अपनी असहमति प्रकट कर कहा कि आज यदि प्रशासन अति कठोर से व्यवहार करता होगा तो भी कुछ काल बीतने के बाद उसमें शिथिलता आएगी। ठीक उसी समय हम सब अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उसका मुकाबला कर सकेंगे और यशस्वी भी होंगे। आज जब शासन कड़ाई से बर्ताव कर रहा है। तब हमने अपना अस्तित्व और संगठन सुरक्षित रखना है। मनोबल ऊँचा रखना है। अपने संगठन की शक्ति और अपना समाज इन दोनों पर पूरा विश्वास रखकर हम कुछ दिन निकालें क्योंकि यह आपातकाल अधिक दिनों तक कायम रह नहीं सकेगा।

प.पू.श्रीगुरुजी के प्रति अत्यादर– एक बार पंत को एक महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित होना था। उस दिन उनके पेट में बहुत गड़बड़ी थी। वे बेचैन थे। मेरी माताजी ने थोड़ी घरेलू दवा उन्हें दी थी। इसलिए थोड़ा आराम हुआ था। वे तो बैठक में गए। बैठक यशस्वी हुई। उस बैठक में जब चर्चा चल रही थी तब एम. एम. जोशी जी ने पंत को उनकी बेचैनी का कारण पूछा था। पंत उनके इस प्रश्न से बहुत अधिक अस्वस्थ हुए। बैठक के बाद जब वे घर वापस आए तो उन्हें अस्वस्थ देखकर मैंने उनकी अस्वस्थता का कारण पूछा। मेरे प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि केवल 3–4 घंटे की पेट की तकलीफ को मैं लोगों से छिपा नहीं सका। किन्तु प.पू. गुरुजी तो शरीर में 103°, 104° फारनहाईट के बुखार को भी छिपा सकते थे और किसी को भी जरा सा भी शक होता नहीं था कि उन्हें बुखार होगा। ऐसा श्रीगुरुजी का व्यवहार था। श्रीगुरुजी के महान व्यक्तित्व के कारण और उनके तपोबल के कारण ही वह उनके लिए सहज था किन्तु मुझे मेरी मर्यादा का इस घटना ने ज्ञान करा दिया और इसलिए मैं बहुत अस्त व्यस्त हूँ।[8]

सर्वांगीण विचार की दृष्टि– हम सब एक बार दोपहर का भोजन प्रारंभ ही करने वाले थे तब मेरे कार्यालय में मेरे ऊपर के अधिकारी का मुझे फोन आया तो मैं उठकर फोन के पास गया और उनके साथ बात करने लगा। उस समय मैं टाटा कन्सास्टिंग इंजिनियर्स कंपनी में प्रधान इंजीनियर के पद पर कार्यरत था। बड़ा ठेका देने के संबंध में हमारी बातचीत 30–40 मिनट तक हुई। ठेका देने के पहले सरासर विचार करना पड़ता है। 3–4 पहलू बड़े महत्व के थे। बात पूरी कर निर्णय क्या लेना यह निश्चित हुआ तब फोन रखकर मैं भोजन करने वापस आया। तब पंत ने पूछा कि इतनी देर क्यों लगी। मैंने हमारी जो चर्चा अधिकारी सहित हुई उसका ब्योरा दिया। पंत ने मेरी बातें सुनकर ठेका देने संबंधी अपना मत दो–तीन मिनट के बाद दिया। मुझे तब आश्चर्य हुआ

कि जो निर्णय हमने 40 मिनट में दिया था। ठीक वही निर्णय पंत ने हमें दो–तीन मिनट में ही दिया था। तब मुझे ज्ञात हुआ कि पंत की सर्वांगीण विचार करने की दृष्टि में अति सहजता थी और अचूक निर्णय लेने की विलक्षण क्षमता उनमें थी।

वाचन में रुचि रात में सोने के पूर्व कुछ पढ़ने की उनकी आदत थी। घर में जो भी मासिक पत्रिका होती थी वे उसे पढ़ लेते थे। किसी भी गंभीर विषय को लेकर कोई पुस्तक हमारे यहाँ तो उन्होंने पढ़ी नहीं थी। कार्यकर्ताओं में बातचीत व चर्चा करते समय अनेकानेक संदर्भों का उल्लेख वे कर देते थे। प्रवास और बैठकों में तथा वार्तालापों के व्यस्त कार्यक्रमों के रहते वे कब किताबों को पढ़ लेते थे यह एक आश्चर्यजनक बात थी। पंत को वाचन में गहरी रुचि थी।

कसरासार विचार का व्यवहार हो– एक बार हवाई अड्डे से मैं ऑटो रिक्शा से घर आया तब रिक्शेवाले ने मुझसे थोड़ा ज्यादा किराया माँगा। उस पर हमारा वाद विवाद चला। उसी समय पंत बाहर जाने के लिए निकले थे तब उन्होंने वह सुन लिया था। फिर वे मुझसे बोले कि थोड़ा ज्यादा किराया माँग रहा है तो उन्हें उतना किराया दे दो। उनसे विवाद मत करो। पैसा ज्यादा लेकर रिक्शावाला चला गया। तब पंत ने मुझसे कहा देखो, तुम तो हवाई जहाज से बहुत किराया देकर आये हो यह रिक्शा वाले की कमाई उस तुलना में कम होती है। इसलिए उसने थोड़े ज्यादा रुपये माँगे तो तुमने दे देने चाहिए। हर बात को कानून के दायरे में बाँध नहीं सकते। इसलिए सारे पहलुओं को विचार में लेकर निर्णय लेना उचित होता है। अपना व्यवहार सरासर विचार करने के बाद ही योग्य ऐसा होना चाहिए।

समाज सुधार की मौलिकता – पंत की सूटकेस एक बार हवाई अड्डे पर चुराई गई। यह बात ध्यान में आते ही वे संबंधित अधिकारी से मिले और तुरन्त कार्रवाई करने की प्रार्थना की। इस अधिकारी ने धोती कुर्ता वाले सामान्य व्यक्ति की तरफ ध्यान नहीं दिया। उनकी प्रार्थना को उपेक्षित किया। बाद में पंत ने उसके ऊपर वाले अधिकारी के पास जाकर बताया और प्रार्थना की कि उन्हें उनकी सूटकेस जल्द ही मिले। किन्तु दुर्भाग्य की बात हुई और वहाँ पर भी पंत को निराशा हाथ लगी। अंत में पंत ने अपने खिसे में से अपनी खासदार की पहचान निकाल कर उस अधिकारी को दिखाई तब कहीं जाकर तेजी से हलचल हुई और 10–15 मिनट में ही पंत की सूटकेस उन्हें मिल गई। इस प्रसंग पर पंत बोले कि जब तक मामूली से काम के लिए प्रलोभन वा भय नहीं दिखाया जाता तक तब काम नहीं होता–यह स्थिति रही तो समाज कैसे प्रगति करेगा? सत्ता में कौन रहते हैं यह मुद्दा गौण है। समाज को ही मूल से परिवर्तित कर सुधारना अनिवार्य है।

कुछ बातें भगवान पर छोड़ें– बाहर के दरवाजे की घंटी बजने पर पंत दरवाजा खोलने के लिए तुरन्त उठकर जाते थे। अनेक बार उन्हें वैसा करने से रोकने के बाद भी वे मानते नहीं थे। उन्हें सुरक्षा विषय की बात कही तो भी वे कहते थे मेरे घर में होने पर कोई मुझे खोजने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें मिलूँगा ही। सतर्क रहना यह बात ठीक है किंतु 24 घंटे अपने सर पर तलवार लटकाकर क्यों रहें? ऊपर वाले पर कुछ बातें छोड़ देनी चाहिए।

घर पर पुलिस आई तब से– आपातकाल में पंत हमारे यहाँ रुके थे। किंतु सुबह बाहर निकलते समय कहकर गए थे कि दोपहर तक वापस लौट आएँगे। किंतु वैसा नहीं हुआ। शाम के साढ़े सात बजे घर पर पुलिस उन्हें खोजने आई। मेरा पूर्व इतिहास उन्होंने पूछा। घर की तलाशी ली। मुझे डर इस बात का लग रहा था कि इतने में पंत अगर घर आए तो पकड़े जाएंगे। किंतु सौभाग्यवश वैसा कुछ हुआ नहीं । पुलिस कमिश्नर ने थोड़ा हमें डाँटा फटकारा और वे चले गए। आधे घंटे के बाद मा. सुरेश राव केतकर घर आए। उन्हें हमने कहा कि पंत को बताइये कि वे अब हमारे घर ना आवें, अन्यथा वे पकड़े जाएँगे। वे भी चले गए। शाम को श्री रमण भाई शाह को हमारे घर के नीचे से ही पकड़ कर ले गए।

उसी दिन शाम के समय हमारे कॉलोनी में ही श्री भट के यहाँ गया और उन्हें सब बताया और कहा कि शाखा में होने वाले कार्यक्रम में मैं नहीं आ पाऊँगा। यह कहकर मैं बाहर आया तो पुलिस ने रोका और पूछा कि कहाँ गए थे। मैंने बताया की भट के घर गया था। तब से सारी फौज उनके घर के चारों ओर निगरानी में लगाई गई। हमारा घर इसलिए निगरानी से बच गया था। उसी रात साढ़े नौ बजे हमारे घर पंत हाथ में बैग लेकर आए। मैंने उन्हें दिनभर की कहानी सुनाई तो वे तुरन्त बैग घर में ही छोड़कर बाहर निकल गए। जब कुछ देर के बाद पंत की लिखी चिट्ठी लेकर एक व्यक्ति बैग लेने आए तब हमने बैग दे दिया। बाद में पंत का हमारे घर आना रुक गया।

भाग्यशाली परिवार– हमारा परिवार बहुत ही भाग्यवान रहा। वह इसलिए कि आपातकाल में श्री माधवराव मुले, श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी, श्री मोरोपंत पिंगले, श्री आबाजी थत्ते हमारे घर 10–15 दिन बारी बारी से आकर रुकते थे, रहते थे। उन्हें सब प्रकार से अच्छा खाना खिलाना, उनका वास्तव्य सुखमय व आराम का करना यह हमारे भाग्य में था। आपात्काल के कारण ही यह संभव हो पाया। अन्यथा यह संभव नहीं हो पाता।

❐

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस

– विकिपीडिया से संकलित

सुभाष चन्द्र बोस (23 जनवरी 1897 – 18 अगस्त 1945) भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिन्द फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया ''जय हिन्द'' का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। ''तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा'' का नारा भी उनका था जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेता जी के नाम से सम्बोधित करते हैं।

कोलकाता के स्वतन्त्रता सेनानी देशबंधु चित्तरंजन दास के कार्य से प्रेरित होकर सुभाष दासबाबू के साथ काम करना चाहते थे। इंग्लैंड से उन्होंने दासबाबू को खत लिखकर उनके साथ काम करने की इच्छा प्रकट की। रवींद्रनाथ ठाकुर की सलाह के अनुसार भारत वापस आने पर वे सर्वप्रथम मुम्बई गये और महात्मा गांधी से मिले। मुम्बई में गांधी मणिभवन में निवास करते थे। वहाँ 20 जुलाई 1921 को गाँधी और सुभाष के बीच पहली मुलाकात हुई। गाँधी ने उन्हें कोलकाता जाकर दासबाबू के साथ काम करने की सलाह दी। इसके बाद सुभाष कोलकाता आकर दासबाबू से मिले।

उन दिनों गाँधी ने अंग्रेज सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन चला रखा था। दासबाबू इस आन्दोलन का बंगाल में नेतृत्व कर रहे थे। उनके साथ सुभाष इस आन्दोलन में सहभागी हो गये। गाँधी द्वारा 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया जिसके कारण 1922 में दासबाबू ने कांग्रेस के अन्तर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। विधानसभा के अन्दर से अंग्रेज सरकार का विरोध करने के लिये कोलकाता महापालिका का चुनाव स्वराज पार्टी ने लड़कर जीता और दासबाबू कोलकाता के महापौर (Mayor) बन गये। उन्होंने सुभाष को महापालिका का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाया। सुभाष ने अपने कार्यकाल में कोलकाता महापालिका का पूरा ढाँचा और काम करने का तरीका ही बदल डाला। कोलकाता में सभी रास्तों के अंग्रेजी नाम बदलकर उन्हें भारतीय नाम दिये गये। स्वतन्त्रता संग्राम में प्राण न्योछावर करने वालों के परिवारजनों को महापालिका में नौकरी मिलने लगी।

बहुत जल्द ही सुभाष देश के एक महत्वपूर्ण युवा नेता बन गये। जवाहरलाल नेहरू के साथ सुभाष ने कांग्रेस के अन्तर्गत युवकों की इण्डिपेण्डेंस लीग शुरू की। 1927 में जब साइमन कमीशन भारत आया तब कांग्रेस ने उसे काले झण्डे दिखाये। कोलकाता में सुभाष ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया। साइमन कमीशन को जवाब देने के लिये कांग्रेस ने भारत का भावी संविधान बनाने का काम आठ सदस्यीय आयोग को सौंपा। मोतीलाल नेहरू इस आयोग के अध्यक्ष और सुभाष उसके एक सदस्य थे। इस आयोग ने नेहरू रिपोर्ट पेश की। 1928 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ। इस अधिवेशन में सुभाष ने खाकी गणवेश धारण करके मोतीलाल नेहरू को सैन्य तरीके से सलामी दी। गाँधी जी उन दिनों पूर्ण स्वराज्य की माँग से सहमत नहीं थे। इस अधिवेशन में उन्होंने अंग्रेज सरकार से डोमिनियन स्टेटस माँगने की ठान ली थी। लेकिन सुभाषबाबू और जवाहरलाल नेहरू को पूर्ण स्वराज की माँग से पीछे हटना मंजूर नहीं था। अन्त में यह तय किया गया कि अंग्रेज सरकार को डोमिनियन स्टेटस देने के लिये एक साल का वक्त दिया जाये। अगर एक साल में अंग्रेज सरकार ने यह माँग पूरी नहीं की तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज की माँग करेगी। परन्तु अंग्रेज सरकार ने यह माँग पूरी नहीं की। इसलिये 1930 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में लाहौर में हुआ तब ऐसा तय किया गया कि 26 जनवरी का दिन स्वतन्त्रता दिवस के रूप में मनाया जायेगा।

26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्र ध्वज फहराकर सुभाष एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलायी और उन्हें घायल कर जेल भेज दिया। जब सुभाष जेल में थे तब गाँधी जी ने अंग्रेज सरकार से समझौता किया और सब कैदियों को रिहा करवा दिया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रान्तिकारियों को रिहा करने से साफ इन्कार कर दिया। भगत सिंह की फाँसी माफ कराने के लिये गाँधी जी ने सरकार से बात तो की परन्तु नरमी के साथ ऐसा बताया जाता है परंतु सत्य कुछ और ही है। सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गाँधीजी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें। लेकिन गांधीजी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने को राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही और भगत सिंह व उनके साथियों को फाँसी दे दी गयी। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष गाँधी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज हो गये।

❐

GOVERNMENT OF INDIA'S DECISIONS

(1) Acceptance of gifts by Government servants on the occasion of their transfer or retirement — Instances have come to the notice of Government in which senior officers and others were presented on the occasion of their retirement or transfer, with expensive gifts for the purchase of which the members of the staff contributed. Permission of Government under Rule 13 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, to accept these gifts was sought on the ground that these were a token of the esteem and affection in which the officers concerned were held.

While a farewell entertainment of a substantially private and informal character may be held in honour of such officers on the eve of retirement or transfer, as permitted under the proviso to Rule 14 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964 and gift of trifling value [as defined in the Explanation to Rule 13 of the above rules] presented and accepted on such occasion, it is hardly healthy or desirable to allow the practice of accepting gifts from the staff.

The Ministry of Finance, etc., are accordingly requested to bring to the notice of all concerned that entertainment or gifts on such occasions should be strictly confined to the limits permitted under the Conduct Rules.

[GL, M.H.A., O.M. No. 25/40/58-Ests. (A), dated the 24th July, 1958.]

Instances have come to the notice of Government in which Government Servants were presented with gifts of more than trifling value on the occasion of their retirement or transfer and the Government servant concerned asked for permission to accept them. It has, therefore, been decided that in future no Government servant should be given permission to accept gifts of more than trifling value at the time of his transfer. There is, however, no objection to his accepting gifts at the time of his retirement from the members of the staff, subject, however, to prior permission of Government, wherever such permission is necessary.

[GI.,M.H.A.,O.M. No. 25/22/62-Ests. (A), dated the 12th November, 1962.]

(2) Familiarity arising out of private hospitality to be avoided. — Recommendation No. 24 contained in Paragraph 6.11 of the report of committee on prevention of Corruption, has been carefully considered in the light of the comments received from the Ministries / Departments. The following decisions were reached in regard to this recommendation:—

(i) The distinction between Economic MInistries and other Ministries may not serve any useful purpose as officers were liable to transfer and a business house may find it worthwhile to invest in an officer even though he were in a non-Economic Ministry, in the hope that this investment would be useful later on.

(ii)It is essential to avoid the familiarity arising out of private hospitality. When in doubt, an officer should abstain from accepting an invitation and he should not accept invitations Particularly from persons who have cases before him.

2. Attantion is also invited to the provisions contained in Note (2) of Rule 13.

3. A doubt was also expressed whether if a Minister accepts an invitation, it should be incumbent on the official to accept it. It has been decided that in such cases it would not be incumbent on the official to accept the invitation.

[Gl., M.H.A., O.M. No. 43/60/64-AVD, dated the 18th January, 1965.]

(3) Invitation for free "inaugural flights" by Governmet servants and members of their families amounts to "gift".- The Air India and the Indian Airlines Corporation sometimes extend invitations to Government servants and members of their families to participate, free og cost, in their inaugural flights. Similar invitations may also be received by Government servants and members of their families from foreign air transport companies operating through India. Such invitations amount to "gift", vide Explanation below Rule 13 (1) of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, and

acceptance of such gifts will attract the provisions of Rule 13 (4) ibid.

It is, therefore, necessary to regulate the acceptance of the gifts referred to above, so as to ensure that these favours do not place the Government servants, exercising a measure of discretion on behalf of Government, in a position where their impartial judgment would be affected, or would seem to be so affected to an outside observer. The Administrative Ministries / Departments should keep this in view while considering requests of individual officers to permit them or the members of their families to accept invitations for free inaugural flights offered by the Air India, the Indian Airlines Corporation or foreign airlines. The Ministry of Civil Aviation should be consulted in all cases before granting or Withholding permission.

Cases of officers of the Alll India Services serving under the Government of India should be referred to the Alll India Service Division of the Ministry of Home affairs who will decide each individual case on consultationy of Civil Aviation,

[G1., M.H.A..O.M. No, F, 25/34/64-Ests. (A), dated the 25th May, 1965.]

The following rules will be observed in giving passage clearance as far as Government servants are concerned:—

(i) Only the officials of the Civil Aviation Department and the Department of Tourism will be allowed to accept these invitatios. The families of the officers shall not, in any case, be permitted to join the inaugural flight.

(ii) In every such case as referred to in (a) above, the orders of the MInister concerned shall also be obtained.

It is requested that this aspect should be kept in view when dealing with requests and applications so that subsequent embarrassment on account of Government's refusal to give passage clearance is avoided.

[G.I., M.F., O.M. No. F. 3 (328)-EC/65, dated October, 1965.]

(4) Acceptance of presents by Government servants at the time of their marriage. — Receipt of presents by Government servants at the time of their marriage, in the form of cash, ornaments, clothes or other articles, otherwise than as consideration for marriage, from relatives and personal friends, will be regulated by sub-rules (2) and (3) of Rule 13 of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964. The receipt of such presents, from persons other than relatives and persona friends will be regulated by dub-rule (1) of Rule 13 ibid., read with sub-rule (4) thereof. Purchases of items of movable property for giving presents at the time of marriage will be regulated by Rule 18 (3) of the Central civil Services (Conduc) Rules, 1964, like any other transaction in movable property.

[G.I., M.H.A., O.M. No. 25/37/65-Ests. (A), dated the 30th August. 1965.]

(5) Acceptance of passage and hospitality by officers from foreign contracting firms not permissible — Government have have had under consideration the question whether an officer may be permitted to accept the cost of passage to a foreign country and hospitality during his stay there by way of free board and lodging, if offered by a foreign firm contracting with the Government either directly or through its agents/representatives in India. The Explanations below Rule (13) (I) of the cntral Civil Services (conduct) Rules, 1964, provide the "gift" shall include free transport, boarding, loging or other servoce or any other pecuniary advantage when provided by any personother than a near relative or personal friend having no official dealings with the Government servant. Note 2 below the said rule further provides that a Government servant shall avoid accepting lavish hospitality or frequent hospitality from any other individual having official dealing with him or from industrial or commercial firms, organizations, etc. In the circumstances. Government have decided

that officers should neither accept, nor be permitted to accept offers of the cost of passage to foreign countries and hospitality by way of free board and lodging there, if such offers are made by foreign firms contracting with Government either directly or through their agents/representatives in India. The only exception to this will be in respect of facilities for training abroad offered by foreign firms (who obtain reimbursement from the foreign Government concerned) as part of aid programmes or as part of agreement of contract entered into by Government of India or a Public Sector Undertaking with a foreign organization.

[G.I., M.H.A., O.M. No. F. 25/4/67-Ests. (A), dated the 3rd April, 1967 and the 6th NOvember 1967.]

(6) Acceptance of gift from subordinates on occasions like weddings, etc.— A question has been raised whether a Government servant can accept gift from a subordinate and if so, whether the limits laid down in Rule 13 of the CCS (Conduct) Rules, 1064, pertain to the value of gifts each individual or from all the officials put together and to say that under sub-rule (3) of Rule 13 of the CCS (Conduct) Rules, 1964. a Government servant can receive gifts from his personal friends not having official dealings with him, on occasions like weddings and is required to make a report to the appropriate authority if the value of such gifts exceed the specified limits, If, therefore gifts are received on occasions like weddings from persons having official dealings with the Government servants, sanction will be necessary for their acceptance under rule 13(4) of the Conduct Rules, if the amount of individual gift exceed the limit specified therein. In the circumstances, technically speaking , no sanction is necessary for acceptance of gifts from subordinates if the limit specified in the rules are not exceeded. However, it does not seem proper on the part of the officer to accept gifts from their subordinates, as such action is against the spirit of Rule 13 (3) and Rule 3 (1) (ii) of the CCS (Conduct) Rules, 1964.

[D.G, P. & T., Letter No. 15/4/67-Disc., dated the 20th September, 1967]

(7) Arms and ammunitions in the prohibited cat accepted as presents.— Gifts offered to Government officials by foreign Governments, foreign institutions, foreign dignitaries, etc., may include arms and ammunitions. The fire-arms and ammunitions described in Category I of Schedule-I appended to Arms Rules, 1962 (copy enclosed), are generally not allowed to be imported into the country for private use. It has accordingly been decided that arms and ammunitions in the prohibited category should not be accepted by Government officials. The concerned official may politely decline the present explaining the import restrictions imposed by the Government of India.

ARMS ACT AND RULES

SCHEDULE-I

Category (1)	Arms (2)	Ammunition (3)
1 (a)	Prohibited ammunition as defined in Section 2 (1) (i) and such other arms as the Central Government may by notification in the Official Gazette, specify to be prohibited arms.	Prohibited ammunition as defined in Section 2 (1) (h) and such other articles as the Central Government may by notification in the Official Gazette, specify to be prohibited ammunition.
(b)	Semi-automatic fire-arms other than those included in Categories I (c) and III (a) smooth-bore guns having barrel of less than 20" in length.	Ammunition for arms of Category 1 (b).
(c)	Bolt action or semi-automatic rifles of .303" or 7.62 mm. bore or any other bore which can chamber and fire srvices ammunitions of .303" or 7.62 mm. calibre musket of .410" bore or any other bore which can fire.410" musket ammunition; pistols, revolvers or carbines of any bore which can chamber and fire .380" or .455" rimmed cartridges or service 9mm or .45" rimless cartridges	Ammunition for fire-arms of Category 1 (c).
(d)	Accessories for any fire-arms designed or adapted to diminish the noise of flash caused bt the firing thereof.	

[G.I. M.H.A., O.M. No. 25/13/65-Ests. (B), dated the 10th December, 1969.]

(8) Acceptance of membership of Books Clubs run by Foreign Agencies.— A question has been raised whether a Government servant should obtain permission of the Government for accepting the membership of book club run by foreign agency. It is clarified that a Government servant should obtain prior permission of the foreign book club entitled the Government servant to receive books, etc., by way of gifts, the question of acceptance of such gifts would be governed by Rule 13 of the CCS (Conduct) Rules, 1964.

[Gl., CS. (Dept. of Per.), O.M. No. 25/16/73-Estt. (A), dated the 3rd July, 1973.]

(9) Acceptance of award / prize by Government servants from private firms and Rotary Clubs.— A question has been raised whether a Government servant may be permitted to accept an award / prize from a Rotary Club or any private firm in appreciation of the outstanding work done by the official.

It has been the consistent policy of the Government that if a Government servant has done some outstanding work, there are various methods, open to Government themselves, to recognize his merit and service and it would not be appropriate for a private body to give a reward, etc. While there is no reason to believe that this position is not understood as such by the Heads of circles, the position is being once again reiterated that no official of this Department be permitted to accept any prize / award from a Rotary Club or a private firm, in appreciation of his performance. Any such offer of a prize or award if and when made, should be declined politely.

[D.G., P. & T., Letter No. 37/3/73-S. P.B.I., dated the 14th September, 1973 and Min. of Works & Housing, O.M. No. AV-484, dated the 15t February, 1974.]

(10) Receipt and acceptance of gifts from foreign dignitaries / sources and retention thereof.— The Foreign Contribution (Regulations) Act 1976 and the Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentations) Regulations, 1978, govern the acceptance, by any person covered under the Act of any gift / presentation, made to him by any foreign source including foreign dignitaries amd the procedure/conditions for its retention. The Department of Personnel and Training have also amended the relevant provisions of the CCS (Conduct) Rules, regarding acceptance of gifts from foreign dignitaries *vide* their notification No. 11013/18/87-Estt. (A), dated the 18th September, 1990, to bring these provisions in line with the provisions under the Foreign Contribution (Regulations) Act, 1976.

2. The relevant excerpts from the Foreign Contribution (Regulations) Act, 1976, CCS (Conduct) Rules and a copy of the Foreign Contribution (Acceptance or Retention of Gifts or Presentations) Regulations, 1978, regarding acceptance of gifts, etc., as members of an Indian delegation from a foreign source, as these exist on date, are enclosed for ready reference.

3. As would be observed from Section 2 (1) (C) of the Foreign Contribution (Regulations) Act, an article of gift, the market value of which, in India, on the date of such gift, does not exceed one thousand rupees, is not treated as "foreign contribution" and is out of the purview of the Act. Acceptance of such gifts is to be regulated under Rule 13 of the CCS (Conduct) Rules. All other gifts, received by any Government servant from a foreign source otherwise than as a member of an Indian delegation shall be dealt with under Section 4 of the said Act.

4. A copy of the Ministry of Home Affairs' Circular No. II/21022/10 (2)/ 82-FCRA-I, dated 6-5-1983, defining the term "Delegation" for the purposes of Foreign Contribution (Regulations) Act, 1976, is also enclosed.

5. The above provisions and instructions may please be brought to the notice of all concerned for information and guidance.6. This issues in supersession of this Ministry's O.M. No. Q/TK/461/9/90, dated 26-10-1990.

❐

Government ORDERS

No.1/1(1)/2023-P&PW (E) Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension, Department of Pension and Pensioners' Welfare, New Delhi, dated 1 January, 2024

Subject: Amendment to CCS (Pension) Rules, 2021 - Allowing female Government servants/female Pensioner to nominate her child/children for family pension in precedence to her husband in the event of marital discord leading to filing of divorce proceedings in a Court of Law or filing of a case under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or Indian Penal Code- reg.

The undersigned is directed to state that, as per the provisions of sub-rule (8) and sub-rule (9) of Rule 50 of CCS (Pension) Rules, 2021, if a deceased Government servant or pensioner is survived by a spouse, family pension is first granted to the spouse and the children and other family members become eligible for family pension, on their turn, only after the spouse of the deceased Government servant/pensioner becomes ineligible for family pension or dies.

2. This Department has been receiving a large number of references from Ministries/Departments, seeking advice as to whether a female Government servant/female Pensioner can be allowed to nominate her eligible child/children for family pension in place of her spouse in the event of marital discord leading to filing of divorce proceedings in a Court of Law or filing of a case under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or under Indian Penal Code.

3. The matter has been examined in consultation with Ministry of Women and Child Development. Accordingly, it has been decided that in case divorce proceedings in respect of a female Government servant/female pensioner are pending in a Court of Law, or the female Government servant/female pensioner has filed a case against her husband under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or under Indian Penal Code, such female Government servant/Female Pensioner may make a request for grant of family pension after her death to her eligible child/children, in precedence to her husband and such request may be considered in the following manner:

(a) Where, in respect of a female Government servant/female pensioner, divorce proceedings are pending in a competent Court of Law, or the female Government servant/female pensioner has filed a case against her husband under Protection of Women from Domestic Violence Act or Dowry Prohibition Act or under Indian Penal Code, the said female Government servant/female pensioner, may make a request in writing to the concerned Head of Office to the effect that, in the event of her death during the pendency of any of the aforesaid proceedings, family pension may be granted to her eligible child/children in precedence to her spouse;

(b) In the event of the death of the female Government servant/female pensioner, who had made a request under clause (a), during the pendency of any of the aforesaid proceedings, the family pension shall be disbursed in the following manner, namely:

(i) Where the deceased female Government servant / female pensioner is survived by a widower and no child/children is eligible for family pension on the date of death of the female Government servant/female pensioner, family pension shall be payable to the widower.

(ii) Where the deceased female Government servant/female pensioner is survived by a widower with a minor child/children or a child/children suffering from disorder or disability of mind including the mentally retarded, the family pension in respect of the deceased shall be payable to the widower, provided he is the guardian of such child/children and if the widower ceases to be the guardian of such child/children, such family pension shall be payable to the child through the person who is the actual guardian of such child/children. Where the minor child, after attaining the age of majority, remains eligible for family pension, the family pension shall become payable to such child from the date on which he/she attains the age of majority.

(iii) Where the deceased female Government servant/female pensioner is survived by a widower with a child/children who has/have attained the age of majority but is or are eligible for family pension, the family pension shall be payable to such child/children.

(iv) After the child/children referred to in clause (ii) and (iii) above cease to be eligible for family pension under Rule 50 of the CCS (Pension) Rules, 2021, family pension shall become payable to other child/children, if any, eligible for family pension.

(v) After all the children cease to be eligible for family pension under Rule 50 of the CCS (Pension) Rules, 2021, family pension shall become payable to the widower till his death or remarriage, whichever is earlier.

4. All Ministries/Departments are requested to bring the contents of this order to the notice of Controller of Accounts/Pay and Accounts Officers and Attached, Subordinate Offices and Autonomous bodies under them.

5. In so far as the persons serving in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders are issued in consultation with Comptroller and Auditor General of India, as mandated under Article 148(5) of the Constitution of India.

6. Formal amendment to Rule $0 of the CCS (Pension) Rules, 2021 will be notified separately.

7. Hindi version will follow. ❐

FTS No: 8108208 File No: S-11011/27/2021 /CGHS(HEC Government of India, Ministry of Health & Family Welfare, Directorate of central Government Health Scheme (CGHS), Hospital Empanelment Cell (HEC) New Delhi, dated 12 January, 2024

Subject: CGHS Package rates code Number where differential pricing is applicable in reference to OM dated 19th December 2023 Revision of CGHS rates for Cardiology procedures inclusion of two new procedure and revision of rates PET CT Scan-regarding.

Reference: Email dated 08.01.2024 from NHA requesting for CGHS rates code No. where differential pricing is applicable

List of CGHS package rates code and treatment procedure name of the revised CGHS rates for Cardiology Procedures, Two new procedures and revision of rates of PET CT Scan vide OM dated 19th December 2023, where differential pricing is applicable as per the terms and condition point No 4 of OM dated 26.11.2014, on Clarification regarding Empanelment & CGHS Rates, wherein it is mentioned that CGHS approved rates list for various treatment procedure are for semi private ward, if the beneficiary is entitled for General ward, there will be a decrease of 10% in these rates; for private ward entitlement there will be an increase of 15% , however, for investigations the rates mentioned in the CGHS list would apply irrespective of the entitlement of the beneficiary.

The rates prescribed below are for semi private ward. CGHS Package rates code where differential pricing of 10% decrease for General Ward entitled Beneficiaries and15% increase for those entitled Private ward is applicable are listed here under.

Sr. No.	CGHS rate Code Number	TREATMENT PROCEDURE CARDIOVASCULAR AND CARDIAC SURGERY & INVESTIGATIONS	Non-NABH Non-NABL Rates in Rupees	NABH / NABL Rates in Rupees
1	544	Balloon coronary angioplasty / Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) / Percutaneous coronary intervention (PCI) with Vascular closure device (VCD)	78,200	92,000
2	545	Balloon coronary angioplasty / Percutaneous transluminal coronary angioplasty (PTCA) / Percutaneous coronary intervention (PCI) \without Vascular closure device (VCD)	71,150	83,725
3	546	Rotablation	47,775	56,206
4	547	Balloon Mitral Valvotomy / Percutaneous transvenous mitral commissurotomy (PTMC)	77,000	90,700
5	548	Cardiac Catheterization (CATH) X	11,510	13,545
6	556	Coarctation dilatation / Balloon dilatation of Aortic coarctation -including cost of Balloon	60,860	71,600
7	558	Temporary Pacemaker Implantation (TPI) (Temporary Cardiac Pacing) Single Chamber	16,320	19,200
8	560	Permanent pacemaker implantation (PPI)-Single Chamber	27,200	32,000
9	561	Permanent pacemaker implantation Dual Chamber	36,550	43,000
10	562	Permanent pacemaker implantation (PPI)-Biventricular	42,180	49,625
11	563	Automatic implantable cardioverter defibrillator (AICD) -Single Chamber	42,500	50,000

12	564	Automatic implantable cardioverter defibrillator (AICD) -Dual Chamber	44,500	52,350
13	565	Combo device implantation	50,150	59,000
17	569	Radiofrequency (RF) ablation conventional	81,600	96,000
18	570	Radiofrequency (RE) ablation Atrial Tachycardia/ with 3-D mapping-All inclusive	1,53,850	1,81,000
19	570	Endonnyocardial biopsy	Deleted	Deleted
20	562	Intra-aortic balloon pump (IABP)- Including Cost of Balloon	42,500	50,000
21	573	Intra vascular coiling	63,750	75,000
22	574	Septostomy- Balloon	25,500	30,000
23	576	Aortic valve balloon dilatation (AVBD)/ pulmonary valve balloon dilatation (PVBD)	47,940	56,400
25	578	Digital subtraction angiography- venogram	12,400	14,610
26	581	Peripheral Angioplasty including Vascular Closure Device (VCD)	46,750	55,500
27	583	Renal Angioplasty	46,750	55,500
30	588	Inferior Vena Cava (IVC) filter implantation (Cost of Filter extra)	25,500	30,000
31	589	ASD/VSD/PDA device closure	Delete	Delete
31	520	Atrial Septal Defect (ASD) closure	84,065	98,900
31	521	Ventricular septal defect (VSD) closure	93,415	1,0,9,900
31	541	Patent ductus arteriosus (PDA), device closure	46,750	55,000
35	601	Coronary angiography	11,240	13,225
36	608	Pericardiocentesis	8,500	10,000
		New CGHS Treatment Procedure under Cardiology included w.e.f. 19.12.2023		
1(2)	1855	Transcatheter Aortic Valve Implantation (TAVI) / Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR) — Procedure Cost	85,000	100,000

❐

F No Z15025/32/2023/DIR/CGHS Govt. of India, Min. of Health & Family Welfare, Department of Health & Family Welfare, Directorate of CGHS New Delhi, dated 19 December, 2023

Subject: Revision of CGHS rates for Cardiology Procedures, inclusion of 2 new procedures and revision of Rates of PET CT Scan-regarding

I am directed to convey the approval of Competent Authority for revision of CGHS rates for Cardiology Procedures , inclusion of 2 new procedures and revision of rates of PET CT Scan as per the details given below:

(all Figures are in Rupees)

Sr. No.	TREATMENT PROCEDURE and Investigations in CARDIOLOGY	CGHS package rates for NABH Hospitals	CGHS package rates for Non - NABH Hospitals
1	Balloon coronary angioplasty/PTCA	92,000	78,200
2	Balloon coronary angioplasty/PTCA without Vascular Closure Device	83,725	71,150
3	Rotablation	56,206	47,775
4	Balloon Mitral Valvotomy / Percutaneous transvenous mitral commissurotomy (PTMC) -	90,700	77,000
5	Cardiac Catheterization (CATH)	13,545	11,510
6	Coaractation dilatation	71,600	60,860
7	Temporary Pacemaker Implantation (TPI) (Temporary Cardiac Pacing) Single Chamber	19,200	16,320
8	Permanent pacemaker implantation (PPI)- Single chamber	32,000	27,200
9	Permanent pacemaker implantation- Dual chamber	43,000	36,550
10	Permanent pacemaker implantation (PPI)- Biventricular	49,625	42,180
11	Automatic implantable Cardioverter defibrillator AICD Single chamber	50,000	42,500
12	Automatic implantable Cardioverter defibrillator AICD Dual chamber	52,350	44,500
13	Combo device implantation	59,000	50,150
14	Diagnostic Electrophysiological studies conventional (including catheter)	66,000	56,100
15	Ambulatory BP monitoring	1,000	1,000
16	External Loop/event recording (maximum up to 7 days)	1,500 first day and 1,000 for subsequent days	1,500 first day and 1,000 for subsequent days
17	Radiofrequency (RF) ablation conventional	96,000	81,600
18	Radiofrequency (RF) ablation Atrial Tachycardia / with 3-D mapping – all inclusive	1,81,000	1,53,850
19	Endomyocardial biopsy	Deleted	Deleted
20	Intra-aortic balloon pump (IABP) including Cost of Balloon	50,000	42,500
21	Intravascular coils	75,000	63,750
22	Septostomy- Balloon	30,000	47,940
23	Aortic valve balloon dilatation (AVBD) / Pulmonary valve Balloon Dilatation(PVBD)	56,400	47,940
24	Digital subtraction angiography-Peripheral artery	14,610	12,400
25	Digital subtraction angiography- venogram	14,610	12,400
26	Peripheral Angioplasty	55,500	46,750
27	Renal Angioplasty	55,000	46,750
28	Intravascular ultrasound (IVUS) –	50,000	50,000
29	Holter analysis	2,500	2,125
30	Inferior Vena Cava (IVC) filter implantation (Cost of Filter extra)	30,000	25,500
31	ASD/VSD/PDA device closure	ASD - 98,000 VSD - 1,09,900 PDA - 55,000	ASD - 84,065 VSD - 93,415 PDA - 46,750
32	Head--up tilt test (HUTT)	4,000	3,400
33	Stress Myocardial Perfusion Imaging(MPI)-exercise	9,000	7,650
34	Stress Myocardial Perfusion Imaging (MPI) – pharmacological	9,000	7,650
35	Coronary angiography	13,225	11,240

36	Pericardiocentesis	10,000	8,500
37	Intracoronary optical coherence tomography (OCT) / Intravascular optical coherence tomography (IVOCT) /Intravascular Ventricular Assist System	65,000	65,000
38	Fractional Flow Reserve (FFR) inclusive of cost of wire	30,000	30,000
	New Procedures included		
1	TAVI/TAVR Implant	12,84,000	12,84,000
	TAVI/TAVR Procedure cost	1,00,000	85,000
2	IVL (Coronary Intra Vascular Lithotripsy / Short wave Lithotripsy) – including GST	2,68,000	2,68,000
	Revised rates for PET-CT Scan		
FDG Whole body PET/CT Scan		11,500	10,000
Brain/Heart FDG PET/CT Scan			
Gallium-68 Peptide PET/CT imaging for Neuroendocrine tumor			

15	567	Ambulatory RF monitoring	1000	1020
16	568	External Loop/event recording (Maximum up to 7 days	1500 first day and 1000 for subsequent days	1500 first day and 1000 for subsequent days
28	584	Intravascular ultrasound (IVUS)	50,000	50,000
37	1794	Intracoronary optical coherence tomography (OCT) / Intravascular optical coherence tomography (IVOCT) Intravascular Ventricular Assist System	65000	65000
38	585	Fractional flow reserve (FFR)- inclusive of cost of wire	30,000	30,000
38	1795	Fractional Flow Reserve (FFR) Wire cost (AIIMS Rates	See code 585	See code 585
1	1854	TAVI /TAVR Implant	12,84,000	12,84,000
2	1855	IVL (Coronary Intra vascular Lithotripsy / Short wave Lithotripsy – including GST	2,68,000	2,68,000

2. These rates are applicable in all CGHS Cities.

3. These rates are in supersession of the hitherto existing CGHS package rates for the above items. The other terms and conditions of empanelment shall remain unchanged.

4. The revised rates shall be applicable from the date of issue of this OM and shall be valid till further orders.

5. This issues with the approval of Competent Authority and concurrence of Integrated Finance Division, Ministry of H&FW vide **CD No. 2820 dated 19.12.2023**.

❐

F.No.31011/01/2024 Pers. Policy A-IV Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions Department of Personnel & Training (Pers. Policy A-IV Section)North Block, New Delhi, Dated: 12th January, 2024

~~Subject:- Clarification regarding admissibility of~~ travel by Tejas trains while availing of LTC-reg.

The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 31011/8/2017-Estt. A.IV dated 19.09.2017 on the subject noted above, which inter-alia provides that the travel entitlements of Government servants for the purpose of LTC shall be the same as that of TA entitlements, as notified vide Department of Expenditure (DoE), MoF's OM No. 19030/1/2017- E.IV dated 13.07.2017, except the air travel entitlement for Level 6 to Level 8 of the Pay Matrix, which is allowed in respect of TA only and not for LTC.

2. This Department has been receiving a number of references including RTI applications regarding admissibility of Tejas trains on LTC.

3. The matter has been examined in consultation with Department of Expenditure (DoE) wherein the DoE has informed that Tejas Rajdhani Express Trains are covered under DoE's OM No. 19030/1/2017-E.IV dated 13.07.2017. Accordingly, it is clarified that in addition to trains mentioned in the DOPT's OM No. 31011/8/2017-Estt.A-IV dated 19.09.2017 only **Tejas Rajdhani Express Trains are covered. Further, it is also clarified that the reimbursement of ticket fare of Tejas Express trains is not allowed under LTC.**

4. The claim of reimbursement in respect of LTC journey is to be settled as per the above instructions, however the cases which have already been settled, need not be reopened.

5. Hindi version will follow.

No. 1/5/2017-Estt (Pay-1) Government of India Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions (Department of Personnel & Training)North Block, New Delhi Dated the 15th March, 2019

❐

Subject:Incentive for acquiring fresh higher qualifications, in the 7th CPC Scenario - reg.

Central Government Servants acquiring fresh higher qualifications after coming into service are granted incentive in the form of one-time lump-sum amount ranging from ₹2000/- to 10,000/-, as provided in this Department's OM No. 1/2/89-Estt. (Pay-1) dated 09.04.1999 and other related OMs.

2. The 7th CPC has reviewed the rates of incentive presently available to employees on this account in addition to pay, and have suggested their rationalization

and simplification in Para 8.9.11 to 8.9.14 of their report.

3. Ministry of Finance, Department of Expenditure (DOE) Resolution No. 1-2/2016-IC dated 25.07.2016 vide Para 7 provided that the matter regarding allowances (except Dearness Allowance) based on the recommendations of the 7th CPC shall be referred to a Committee under the Chairmanship of Finance Secretary, and until a final decision thereon, all allowances including this incentive were required to be paid at the existing rates in the existing pay structure (the pay structure based on 6th CPC) as if the pay has not been revised w.e.f. 1st January, 2016.

4. The decision of the Government on various allowances based on the recommendations of the 7th CPC and in the light of the recommendations of the Committee under the Chairmanship of Finance Secretary has been issued as per the Resolution No. 11-1/2016-IC dated 06.07.2017 of DOE.

5. The President is pleased to decide that in supersession of all the existing orders/OMs/ instructions/guidelines on the subject of granting incentive for acquiring fresh higher qualifications, the following one-time lump-sum rates as incentive for acquiring fresh higher qualification by a Government employee shall be permissible for courses in fields that are directly relevant to the employee's job:

Sr No.	Qualification	Amount
1	Ph.D. or Equivalent	30,000/-
2	P.G. Degree / Diploma of Duration more than 1 Year or Equivalent	25,000/-
3	P.G. Degree / Diploma of Duration 1 Year or less, or Equivalent	20,000/-
4	Degree / Diploma of Duration more than 3 Year or Equivalent	15,000/-
5	Degree / Diploma of Duration 3 Year or less or Equivalent	10,000/-

6. Professional courses directly relevant to the functional requirement of the Organization / Ministry / Department but not covered by any one of the categories mentioned inpara 5 above, shall be notified specifically under Sl. No. 4 or 5 of para 5 above, by the concerned Ministry/Department in consultation with their respective IFD.

7. Ministries/Departments are free to choose courses on their own. However, the grant of incentive in respect of above qualifications will be subject to the fulfillment of the criteria laid down in para 8 below. The grant of incentive for the qualifications listed above shall be considered by the administrative authorities in consultation with their IFD and necessary orders shall be issued after ensuring that the criteria laid down in para 8 below are fulfilled.

8. Criteria/guidelines for granting incentive for acquiring fresh higher qualifications, in the 7th CPC Scenario, are as under:

8.1. The incentive will not be available for the qualifications which are laid down as essential. or desirable qualifications in the recruitment rules for the post.

8.2. No incentive shall be allowed for acquiring higher qualification purely on academic or literary subjects. The acquisition of the qualification should be directly related to the functions of the post held by him/her, or to the functions to be performed in the next higher post. There should be direct nexus between the functions of the post and the qualification acquired and that it should contribute to the efficiency of the government servant.

8.3. The quantum of incentive will be uniform for all posts, irrespective of their classification or grade or the department.

8.4. The incentive shall not be admissible where the government servant is sponsored by the government or he/she avails study leave for acquiring the qualification.

8.5. The incentive would be given only for higher qualification acquired after induction into service.

8.6. No incentive would be admissible if an appointment is made in relaxation of the educational qualification. No incentive would be admissible if employee acquires the requisite qualification for such appointment at a later date.

8.7. The qualifications meriting grant of incentive should be recognized by University Grants Commission, respective regulatory bodies like AICTE, Medical Council of India, etc. set up by Central/State Government or recognized by the Government.

8.8. The incentive shall be limited to maximum two times in an employee's career, with a minimum gap of two years between successive grants.

8.9. The Government servant should prefer the claim within six months from the date of acquisition of the higher qualification.

9. The incentive as per this OM will be admissible for above qualifications acquired on or after 01.07.2017.15/03/2018

10. Government Servants, who have acquired the fresh higher qualification on or after 01.07.2017 till the date of issuance of this OM, may also claim these incentives within six months from the date of issuance of this OM.

11. Insofar as the persons working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

12. Hindi Version will follow.

❐

ROLL OF TRADE UNION

Why trade union necessary in industry?

Trade unions play a crucial role in industries worldwide, serving as a vital force that advocates for the rights and well-being of workers. The necessity of trade unions in industries stems from their ability to address the inherent power imbalance between individual workers and employers, striving to create a fair and equitable working environment. This will explore the reasons why trade unions are necessary in industries, covering aspects such as collective bargaining, worker protection, advocacy for rights, and adaptation to changing work dynamics.

Collective bargaining is a cornerstone of trade unions' significance in industries. By organizing workers into a cohesive unit, unions enable collective negotiations with employers on various employment-related matters. This process allows workers to have a stronger voice in determining their working conditions, wages, and benefits. Without unions, individual employees may lack the bargaining power to secure favorable terms, leading to potential exploitation and disparities in the workplace.

Through collective bargaining, trade unions seek to establish agreements that not only benefit their members but contribute to a more stable and productive industrial landscape. These negotiations often result in the establishment of fair wages, reasonable working hours, and improved safety standards. The mutual agreements reached through collective bargaining contribute to a harmonious relationship between employers and employees, fostering a more positive and cooperative workplace environment.

Worker protection is another fundamental aspect that highlights the necessity of trade unions in industries. Unions act as advocates for the rights and well-being of their members, working to ensure that employees are treated fairly and with dignity. This involves addressing issues such as workplace safety, job security, and protection against unfair labor practices. Trade unions actively engage in shaping and influencing labor laws and regulations to establish a legal framework that safeguards the rights of workers.

In the absence of trade unions, workers may find themselves vulnerable to arbitrary decisions by employers, with limited avenues for addressing grievances. Unions provide a structured mechanism for employees to raise concerns collectively, reducing the likelihood of exploitation and fostering a sense of security among the workforce. The presence of trade unions acts as a deterrent against unfair employment practices, as employers are aware that workers have organized representation to protect their rights.

Advocacy for workers' rights is a pivotal function of trade unions in industries. Beyond the immediate concerns of wages and working conditions, unions play a crucial role in championing broader social and economic justice issues. This includes advocating for equal opportunities, combating discrimination, and addressing systemic issues that affect the overall well-being of workers. Unions contribute to creating a more just and inclusive society by leveraging their collective strength to challenge practices that perpetuate inequality and injustice in the workplace.

Trade unions also serve as educational and support platforms for their members, offering resources and information to empower workers. This includes providing legal assistance, offering training programs, and facilitating skill development initiatives. By enhancing the capabilities of their members, unions contribute to creating a more skilled and adaptable workforce, which is essential in the face of technological advancements and evolving industry demands.

The adaptability of trade unions to changing work dynamics further underscores their necessity in industries. As the nature of work undergoes transformations, such as the rise of the gig economy and remote work, unions are evolving to address the unique challenges these changes bring. Unions are exploring innovative approaches to represent and protect workers in non-traditional employment arrangements, ensuring that all workers, regardless of their work structure, have a collective voice in shaping their working conditions.

In industries where technological advancements and automation may impact job security, trade unions serve as advocates for fair transitions. They negotiate with employers to establish policies that address the potential displacement of workers, advocating for retraining programs, job placement assistance, and other measures to support those affected. This adaptability is crucial in maintaining the relevance and effectiveness of trade unions in an ever-evolving industrial landscape.

In conclusion, the necessity of trade unions in industries is evident in their multifaceted role as advocates for workers' rights, facilitators of collective bargaining, and adaptors to changing work dynamics. Trade unions contribute to creating fair and stable workplaces, ensuring that employees have a collective voice in shaping their working conditions. As industries continue to evolve, trade unions remain essential in championing the interests of workers and promoting a more just and equitable society.

❐

भा.प्र.म. संघ के पदाधिकारियों द्वारा सदस्यता सत्यापन हेतु जनसम्पर्क

RNI No. MAHBIL/2002/8760 Publication Date : 30 Jan. 2024
MONTHLY NEWS PAPER
Postal Regd. No. Misc-II/C.P.M//007/K.PH.O./2020 dt 29-12-2020 (for 2021-23)• Posted on Dt. 26,27th Monthly

Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh

(An Industrial Unit of BMS)
Recognized by Ministry of Defence, Govt. of India.

PRATIRAKSHA BHARATI

SPECIAL BULLETIN

Date:-07|Feb|2024 Sr.No- 02/2024

CONGRATULATIONS

In the works Committee election held at DMSRDE kanpur BPMS affiliated union won the majority by 03/05 seats.

On 3rd Feb 2024 in the Works Committee Election held at 223 ABO Depot Suranusi, BPMS affiliated union won the 04/08 seats.

2A, Navin Market, Kanpur-208001. Email: info@bpms.org.in / gensecbpms@yahoo.co.in

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें इस पते पर भेजिये।

बुक पोस्ट

If undelivered please return to :

"Pratiraksha Bharti"
C/o. Bharatiya Pratiraksha Mazdoor Sangh
2, Naveen Market, Kanpur - 208 001
Mob. : 9450153677, Tel./Fax : 0512-2332222
Website : www.bpms.org.in
E-mail : gensecbpms@yahoo.co.in, cecbpms@yahoo.in

Publisher and Owner : Bhartiya Pratiraksha Mazdoor Sangh, 2 Naveen Market, Kanpur-208001
Printed at Chhaya Press 8/208, Arya Nagar, Kanpur-208002 ● Mob. : 9839223650